भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1657

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।

7 श्रावण, 1948 (शक)

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

1657.श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्री गोपाल जी ठाकुरः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री गोडम नागेशः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विगत एक वर्ष के दौरान उत्पादन मे जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और सरकार की अन्य पहलों के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, चालू और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का राज्य/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है।
(ख) घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन, निर्यात और मूल्य संवर्धन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।
(ग) इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण, अनुसंधान एवं नवाचार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएमएमई) की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या पहले की गई हैं, और
(घ) रोजगार सृजन, निवेश और एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत के उभरने पर इन पहलों का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं।

सरकार ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एक सुविचारित रणनीति अपनाई - जिसकी शुरुआत तैयार उत्पादों के निर्माण से हुई, इसके बाद उप-संयोजन, घटकों और अंततः मशीनरी और उपकरण शामिल हुए। साथ ही, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को समर्थन देने के लिए आवश्यक अवसरंचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। पिछले 12 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में काफी विस्तार हुआ है, जिसे निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है:

#	2014-15	2025-26	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (₹)	~1.9 लाख करोड़	~13.11 लाख करोड़	7 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (₹)	~38 हजार करोड़	~4.24 लाख करोड़	11 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का उत्पादन (₹)	~18 हजार करोड़	~6.27 लाख करोड़	33 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का निर्यात (₹)	~15 सौ करोड़	~ 2.59 लाख करोड़	165 गुना वृद्धि

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 11.32 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले एक वर्ष में 15.8 % की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर से बढ़ रहा है।

मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू उत्पादन, निर्यात और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वृद्धि संभव हुई है। कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना
- आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (स्पेक्स)
- भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम।
- भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश।
- इस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति

<u>बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम) के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना</u>

भारत सरकार ने देश में मोबाइल फोन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम) के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की।

एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना के तहत प्रदर्शन (मार्च, 2026 तक) निम्नानुसार है:

श्रेणी	**5 वर्ष के लिए लक्ष्य**	**मार्च 2026 तक वास्तविक रिपोर्ट (संचयी)**
निवेश (रु. करोड़)	7,000	20,587 (294%)
उत्पादन (करोड़ रुपये)	8,12,550	11,61,581 (142%)
निर्यात (रु. करोड़)	4,87,530	6,43,323 (132%)

- स्मार्टफोन, जो वर्ष 2014 में शीर्ष 100 निर्यातित वस्तुओं में शामिल नहीं थे, अब पेट्रोलियम, रत्न और आभूषणों को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की शीर्ष निर्यातित व्यक्तिगत वस्तु बनकर उभरे हैं।
- भारत अब उस स्थिति पर पहुंच गया है जहां भारत में उपयोग किए जा रहे 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जाते हैं।
- भारत आज वॉल्यूम के मामले में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है।
- देश 2014 में मोबाइल फोन के निवल आयातक होने से अब निवल निर्यातक बनने की स्थिति में पहुंच गया है।
- पीएलआई-एलएसईएम ने देश भर में मोबाइल विनिर्माण इकोसिस्टम में लगभग 96,000 करोड़ रुपये (लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश को उत्प्रेरित किया है।
- एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना के बाहरी मूल्यांकन अध्ययन ने बताया कि, उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) बढ़कर 23% हो गया।

एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना के तहत राज्यवार अनुमोदित आवेदकों का विवरण **अनुबंध-I में दिया गया है।**

<u>आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0</u>

भारत सरकार ने आईटी हार्डवेयर (लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, आदि) के लिए एक सुदृढ़ घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने, आयात निर्भरता को कम करने और भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनाने के लिए 2023 में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना

2.0 भी शुरू की है। अब तक, इन योजनाओं से कुल संचयी उत्पादन 24,385.89 करोड़ रुपये हुआ है, कुल संचयी निवेश 1056.36 करोड़ रुपये और कुल संचयी रोजगार 5,216 (प्रत्यक्ष नौकरियां) हुआ है।

आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 के तहत राज्यवार अनुमोदित आवेदकों का विवरण **अनुबंध-II में दिया गया है।**

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करने और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित पहलें की हैं:

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)

सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम को और गहरा करने और देश में सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए ईसीएमएस लॉन्च किया।

इसका उद्देश्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), निष्क्रिय घटकों, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घटकों, उप-असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, ऑप्टिकल ट्रांसीवर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान जैसे प्रमुख घटकों में निवेश को आकर्षित करना है।

इस योजना में भारत में घरेलू/वैश्विक निर्माताओं से 59,350 करोड़ रुपये के निवेश और योजना अवधि के दौरान 91,600 के प्रत्यक्ष रोजगार की परिकल्पना की गई थी।

अब तक, ईसीएमएस के तहत 23 उत्पादों के लिए कुल 75 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृत इकाइयों से 61,671 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने, 4.51 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित उत्पादन पैदा करने और 65,040 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

सरकारी योजनाओं ने कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को सृजित किया है जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत हो गए हैं। एमएसएमई इन वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण की विभिन्न सहायक गतिविधियों में उनका समर्थन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत 85 से अधिक एमएसएमई को सहायता दी जा चुकी है।

सेमीकॉन 2.0

इसके अलावा, घरेलू मूल्यवर्धन में सुधार और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों में बड़े इकोसिस्टम विकास के साथ-साथ सरकार ने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की सामग्री के बिल का एक बड़ा हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 1.64 लाख करोड़ रुपये के कुल प्रतिबद्ध निवेश के लिए 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 3 परियोजनाओं ने पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम की सफलता के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2026 को 1,27,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी। सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य भारतीय डिजाइन किए गए चिप्स के डिजाइन और विकास में तेजी लाना, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयों (एफएबी) का विस्तार करना, उन्नत पैकेजिंग और सहायक सामग्री और गैसों, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण द्वारा बड़े सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में रोजगार सृजन

मौजूदा स्थिति में, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र ~25 लाख नौकरियों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) का समर्थन करता है, जो औद्योगिक रोजगार के अवसर पैदा करने में क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अकेले मोबाइल विनिर्माण इकोसिस्टम वर्तमान में मूल्य श्रृंखला में लगभग 12 लाख लोगों (प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों) को रोजगार सृजित करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र लैंगिक-समावेशी औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसमें कुछ उच्च-परिशुद्धता वाले मोबाइल फोन विनिर्माण खंडों में कुल कार्यबल का लगभग 70% हिस्सा महिला कार्यबल के रूप में कार्यरत है।

***

अनुबंध-I

एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना के तहत राज्यवार स्वीकृत आवेदक

क्र.सं.	राज्य	आवेदकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2
2	दिल्ली	1
3	गुजरात	1
4	हरियाणा	1
5	हिमाचल प्रदेश	1
6	कर्नाटक	6
7	केरल	1
8	महाराष्ट्र	7
9	राजस्थान	1
10	तमिलनाडु	4
11	तेलंगाना	1
12	उत्तर प्रदेश	6
	कुल	32

अनुबंध-II

आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 के तहत राज्यवार स्वीकृत आवेदक

क्र.सं.	राज्य	आवेदकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1
2	दिल्ली	1
3	गुजरात	1
4	हरियाणा	2
5	कर्नाटक	2
6	केरल	1
7	मध्य प्रदेश	1
8	महाराष्ट्र	3
9	पांडिचेरी	1
10	राजस्थान	1
11	तमिलनाडु	6
12	तेलंगाना	1
13	उत्तर प्रदेश	6
	कुल	27

*****